

SHODH SAMAGAM

ISSN : 2581-6918 (Online), 2582-1792 (PRINT)



छत्तीसगढ़ में सार्वजनिक वितरण की वर्तमान प्रणाली का मूल्यांकन

शारदा वर्मा, शोधार्थी, अर्थशास्त्र अध्ययनशाला
हेमचंद्र यादव विश्वविद्यालय, दुर्ग, छत्तीसगढ़, भारत
आर. एन. सिंह, (Ph.D.), शोध निर्देशक
शास. विश्वनाथ यादव तामस्कर स्नातकोत्तर स्वशासी महाविद्यालय, दुर्ग, छत्तीसगढ़, भारत

ORIGINAL ARTICLE



Corresponding Authors

शारदा वर्मा, शोधार्थी, अर्थशास्त्र अध्ययनशाला
हेमचंद्र यादव विश्वविद्यालय, दुर्ग, छत्तीसगढ़, भारत
आर. एन. सिंह, (Ph.D.), शोध निर्देशक
शास. विश्वनाथ यादव तामस्कर स्नातकोत्तर स्वशासी
महाविद्यालय, दुर्ग, छत्तीसगढ़, भारत

shodhsamagam1@gmail.com

Received on : 18/01/2021

Revised on : -----

Accepted on : 25/01/2021

Plagiarism : 06% on 18/01/2021



Plagiarism Checker X Originality Report

Similarity Found: 6%

Date: Monday, January 18, 2021

Statistics: 126 words Plagiarized / 2052 Total words

Remarks: Low Plagiarism Detected - Your Document needs Optional Improvement.

^^NRrhx<+ esa lkoZtfud forj.k dh orZeku iz.kkyh dk ewY;kadu^^ ^^lkoZtfud forj.k
iz.kkyh ds fy, NRrhx<+ dkss feyus okyk jkV⁹h; iqjLdkj eqj; :lk ls jkT; ljdkj jkjk fd, x, fujarj
.oa vFkd iz;kksa dk ifj.kke gSA gekjs rRdkyhu iz/kkuea=h ekuuh; Jh ujsUnz eksnh th us
NRrhx<+ dh lkoZtfud forj.k iz.kkyh dks ns" k dh lcls vPNh forj.k iz.kkyh dgk gSA bl
iz.kkyh esa lalks/ku djs le; 1 twu 1997 dks Hkkjr ljdkj jkjk milHkksDrkksa dkss [kkjkUu]
"kDdj dsjksflu vkfn olrq,a mfr nj ij mfr ewY; dh nqdkusa ds ek;/e ls miyC/k djks

शोध सार

“सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए छत्तीसगढ़ को मिलने वाला राष्ट्रीय पुरस्कार, मुख्य रूप से राज्य सरकार द्वारा किए गए निरंतर एवं अथक प्रयासों का परिणाम है। हमारे तत्कालीन प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेन्द्र मोदी जी ने छत्तीसगढ़ की सार्वजनिक वितरण प्रणाली को देश की सबसे अच्छी वितरण प्रणाली कहा है। इस प्रणाली में संसोधन करते समय 1 जून 1997 को भारत सरकार द्वारा उपभोक्ताओं को खाद्यान्न, शक्कर, केरोसिन आदि वस्तुएं उचित दर पर, उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से उपलब्ध कराने हेतु, लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली लागू की गयी और इसी उद्देश्य को तेजी से पूरा करने के लिए छत्तीसगढ़ राज्य शासन द्वारा 23 सितंबर 2004 को प्रदेश में छत्तीसगढ़ सार्वजनिक वितरण प्रणाली नियोजन आदेश 2004 लागू किया गया। समय के साथ इस प्रणाली में पारदर्शिता और उपभोक्ताओं को अधिक सुविधा प्रदान करने के लिए उचित मूल्य की दुकानों में ऑनलाइन सेवाएं वर्ष 2007 से शुरू कर दी गयी। इस प्रकार छत्तीसगढ़ सरकार लगातार वितरण प्रणाली में सुधार करती रही और यही प्रयास राज्य सरकार को अभी तक 7 राष्ट्रीय स्तर के पुरस्कार दिला चुकी है, जिसमें प्रधानमंत्री अवार्ड 2008-09 सहित अन्य अवार्ड भी शामिल है। आज पुरे देश में प्रथम स्थान पर आरूढ़ छत्तीसगढ़ की वितरण प्रणाली सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है।”

मुख्य शब्द

सार्वजनिक वितरण प्रणाली।

प्रस्तावना

देश 15 अगस्त 1947 को अंग्रेजी सत्ता से तो

January to March 2021 www.shodhsamagam.com

A Double-blind, Peer-reviewed, Quarterly, Multidisciplinary and Multilingual Research Journal

Impact Factor
SJIF (2020): 5.56

1344

राजनीतिक रूप से आजाद हो गया किंतु गुलामी की मानसिकता से मुक्त होने की शायद अब भी जरूरत थी। स्वतंत्रता के समय से हमें दो बड़ी चुनौतियां गरीबी और खाद्य सुरक्षा विरासत में मिली। एक नजर से देखा जाए तो इन समस्याओं को हल करना विकास का पहला लक्ष्य बन गया था। सरकार ने अनाज की खरीद और वितरण व्यवस्था को संतुलित करने का पूरा प्रयास किया और आज तक करती आ रही है। इसी खाद्य भंडारण की नीति को क्रियान्वित करने के लिए एक व्यवस्था का जन्म हुआ जिसे सार्वजनिक वितरण प्रणाली के नाम से जाना गया।

विश्व के हर देश की सरकार यह चाहती है कि उनके देश की जनता स्वस्थ रहें, उनको अच्छा भोजन मिले लेकिन बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण लोगों में गरीबी, भुखमरी बढ़ती जा रही है। इस समस्या को देखते हुए सरकार ने न्यूनतम वर्ग, मध्यम वर्ग के लोगों को भोजन देने का निर्णय लिया। जिससे उनका जीविकोपार्जन हो सके। सार्वजनिक वितरण प्रणाली खाद्यान्नों की कमी को दूर करने तथा उचित मूल्य पर खाद्यान्नों की पूर्ति करने के लिए बनाई गई है। शुरुवात में इसका लाभ समाज के हर तबके, हर व्यक्ति को मिलता था। ऐसा कोई मापदंड आधारित भेद नहीं था कि केवल गरीबों को ही सार्वजनिक वितरण प्रणाली का लाभ मिलेगा, परन्तु बढ़ती हुई जनसंख्या के बीच न्यूनतम वर्ग एवं मध्यम वर्ग की पहचान करके उनको निम्न दरों पर राशन उपलब्ध कराने की चुनौती को पूरा करने इस प्रणाली में संशोधन करके इसका नाम लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली कर दिया गया।

पूरे देश में अनाज और अन्य सामग्रियों का वितरण करने के लिए सरकारी उचित मूल्य की दुकानों का जाल बिछाया गया। इन सरकारी दुकानों से गेहूं, चावल, शक्कर, मिट्टी का तेल, सूती कपड़े, बच्चों की स्कूल सामग्री, साबुन जैसी जरूरी सामग्रियां मिला करती थी। इस व्यवस्था का मकसद लोगों की न्यूनतम जरूरतों को उचित मूल्य पर पूरा कराना था। सरकार इस व्यवस्था को रियायत देती रही है, रियायत के मायने यह है कि सरकार ज्यादा मूल्य पर बाजार से सामान खरीद कर कम मूल्य पर लोगों को उपलब्ध कराती है। कई सालो पहले ही सार्वजनिक वितरण प्रणाली, देश में खाद्य अर्थव्यवस्था के मैनेजमेंट के लिए सरकार की नीति का महत्वपूर्ण अंग बन चुकी है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली प्रत्यक्ष रूप से एक महत्वपूर्ण कदम है जिससे गरीब वर्ग को ऊपर उठाने का एक सराहनीय प्रयास किया जा रहा है क्योंकि सरकार चाहती है गरीबी को खत्म किया जाए। सभी व्यक्ति को तन ढकने के लिए वस्त्र, सिर के लिए छत तथा भुख मिटाने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। कम वस्त्र के बिना व्यक्ति का जीवन संभव है, परन्तु भोजन के बिना जीवन असंभव है। इसलिए व्यक्ति रोटी के लिए कठिन मेहनत करता है साथ ही सरकार पर भी लोगों को खाद्य मुहैया कराने का दायित्व होता है।

सरकार यह जो कल्याणकारी योजना उपलब्ध करा रही है, उससे निम्न वर्ग के लोगों तथा मध्यम वर्ग के लोगों का जीविकोपार्जन हो रहा है। यह प्रणाली केन्द्र और राज्य सरकार द्वारा संयुक्त रूप से चलायी जा रही है। केन्द्र सरकार ने भारतीय खाद्य निगम के द्वारा खाद्यान्नों की खरीद, भंडारण, ढुलाई और आवंटन करने की जिम्मेदारी ली है तथा राज्य सरकार, राज्य के अंदर आबंटन, गरीबी रेखा के नीचे परिवार की पहचान जैसे कार्य करती है। इसमें गरीब परिवारों को बीपीएल राशन कार्डधारी के नाम से चिन्हित किया जाता है। राज्य सरकार के माध्यम से राशन कार्ड जारी किया जाता है। उचित समय पर दुकानों का पर्यवेक्षण करने की भी जिम्मेदारी राज्य सरकार की होती है। जनता की सुविधा का ध्यान रखते हुए हितग्राहियों को खाद्य सामग्री उचित मूल्य की दुकानों पर, उचित मूल्य पर एवं उचित समय पर उपलब्ध कराना सरकार का दायित्व होता है। छत्तीसगढ़ राज्य खाद्य निगम किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान खरीदी की सुविधा देकर उनको अनाज का समर्थन मूल्य प्रदान कर, वितरण प्रणाली को सरल बनाने का प्रयास कर रही है।

इस प्रणाली को सरकार का प्राथमिक समाज कल्याण और गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम के अंतर्गत माना जाता है। इसे खाद्यान्न बाजार में मूल्यों में स्थिरता लाने की व्यवस्था के तौर पर शुरू किया गया था। परन्तु अब खाद्य सामग्री जैसे गेहूं, चीनी, चावल, केरोसीन की आपूर्ति कराना, गरीबों की दशा तथा उसके पोषण की स्थिति में सुधार और बाजार मूल्यों पर नियंत्रण करना इसका उद्देश्य बन गया है।

शोध साहित्य का पुनरावलोकन

मिश्रा चंद्रशेखर ने वर्ष 1991 दिसम्बर में अपने लेख "सार्वजनिक वितरण प्रणाली प्रबंधन में सुधार आवश्यक" में लिखा है कि ग्रामीण समुदाय को विशेषकर सुदूर, दुर्गम एवं पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को अनिवार्य वस्तुओं विशेषकर खाद्यान्न, चीनी, मिट्टी तेल, खाद्य तेल, नमक तथा कपड़े की आपूर्ति की आवश्यकता को नजर अंदाज नहीं किया जा सकता। प्रधान मंत्री जी ने इस वर्ष स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर अन्य महत्वपूर्ण विषयों के साथ सार्वजनिक वितरण प्रणाली पर अपने विचार रखे।

डॉ. जगदीप सक्सेना ने फरवरी वर्ष 2017 में अपने लेख "भारत में खाद्य सुरक्षा दशा दिशा और भावी परिदृश्य" में लिखा है कि आज हमारे देश के अन्न भंडारों में लगातार बढ़ती आबादी को पर्याप्त भोजन उपलब्ध कराने की और किसी अकास्मिता से निपटने के लिए पर्याप्त अन्न मौजूद हैं। हरे भरे खेतों में उपजे अनाज को देश के कोने-कोने तक पहुंचाने और आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को कम कीमत पर अनाज उपलब्ध कराने की एक मजबूत प्रणाली भी काम कर रही है।

ए. एन. अग्रवाल ने वर्ष 2018 में अपने लेख "खाद्य समस्या और सार्वजनिक वितरण प्रणाली" में लिखा है कि देश में ऐसे लोगों की संख्या बहुत अधिक हैं जिन्हें पर्याप्त भोजन नहीं मिल पाता, यही नहीं बल्कि जो भोजन उन्हें मिलता है उसमें भी पोषक तत्वों का प्रायः अभाव रहता है। खाद्यान्न की यह समस्या गरीबी के लिए बहुत गंभीर बनी हुई है। इस समस्या के समाधान हेतु उचित दर पर दुकानों के द्वारा गरीब लोगों को सस्ते भाव में अनाज सुलभ कराया जाता है।

शोध अध्ययन का उद्देश्य

1. सार्वजनिक वितरण प्रणाली में गरीबों का जीवन स्तर में हुए परिवर्तनों का अध्ययन करना।
2. सार्वजनिक वितरण प्रणाली का रोजगार एवं पोषण पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन करना।
3. सार्वजनिक वितरण प्रणाली की सार्थकता का अध्ययन करना।
4. सार्वजनिक वितरण प्रणाली की समस्याओं का सार्थक सुझाव प्रस्तुत करना।

शोध परिकल्पना

1. नियोजित विकास के काल में खाद्यान्न उत्पादन में पर्याप्त वृद्धि हुई है।
2. पर्याप्त खाद्यान्न के उत्पादन के बावजूद भी खाद्यान्न समस्या बनी हुई है।
3. खाद्य वितरण हेतु बनाई गई सार्वजनिक वितरण प्रणाली की व्यवस्था कारगर है।
4. सार्वजनिक वितरण की वर्तमान प्रणाली आवश्यक अपेक्षा में अनुकूल हैं।

शोध प्रविधि

प्रस्तुत अध्ययन को दो उपभागों में बांटा गया है।

1. अध्ययन क्षेत्र का परिचय
 2. आंकड़ों का संकलन
1. **अध्ययन क्षेत्र का परिचय :** भारत के हृदय में बसा छत्तीसगढ़ जिसे धान का कटोरा कहा जाता है। यह उसकी समृद्धि का परिचायक है। प्राकृतिक सुंदरता, सरलता तथा उदारता से ओतप्रोत, नैसर्गिक सौंदर्य संजोए हुए कल-कल संगीत सुनाती नदियां एवं जलप्रपात, लोक संगीत और लोकधुन, जनजाति सभ्यता का ये संगम छत्तीसगढ़ की धरोहर है। मध्यप्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000 के अंतर्गत भारत के हृदय प्रदेश मध्यप्रदेश से पृथक होकर 1 नवम्बर 2000 को छत्तीसगढ़, भारतीय संघ का 26 वां राज्य बन गया। समुद्री घोड़े की आकृति लिए हुए छत्तीसगढ़ इस क्षेत्र को ऐतिहासिक गौरव गाथा कह रहा है। प्राकृतिक ऐतिहासिक काल से आधुनिक काल तक, दक्षिण कौशल से छत्तीसगढ़ तक का सफर अपनी एक विशिष्ट पहचान लिए हुए हैं। छत्तीसगढ़ आज 20 वां वर्ष की युवावस्था को प्राप्त करते हुए वर्तमान में ना केवल राष्ट्रीय अपितु

अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी अपनी गरिमा बिखेर रहा है।

2. **अध्ययन क्षेत्र का परिचय :** प्रस्तुत अध्ययन का शीर्षक छत्तीसगढ़ में सार्वजनिक वितरण प्रणाली की वर्तमान प्रणाली का मूल्यांकन है। यह शोध अध्ययन द्वितीयक समंको पर आधारित हैं। द्वितीयक समंको के स्रोत छत्तीसगढ़ राज्य सरकार के विभिन्न प्रकाशन एवं विभागों के माध्यम से लिया गया हैं।

तालिका क्रमांक 1 : छत्तीसगढ़ में जारी राशनकार्ड की जानकारी

क्रमांक	राशन कार्ड के प्रकार	राशन कार्ड की संख्या
1.	अंत्योदय कार्ड	1395289
2.	निराश्रित कार्ड	38282
3.	अन्नापूर्णा कार्ड	6168
4.	प्राथमिकता कार्ड	4202536
5.	निःशक्तजन कार्ड	9767
6.	(एपीएल) सामान्य कार्ड	877958
कुल योग		6530000

(स्रोत : छत्तीसगढ़ खाद्य विभाग)

उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट होता है कि छत्तीसगढ़ में राशन कार्ड की कुल संख्या 6530000 है अंत्योदय कार्ड की संख्या 1395289, निराश्रित कार्ड की संख्या 38282 है, अन्नपूर्णा कार्ड की संख्या सबसे कम 6168 है। उसी प्रकार निःशक्तजन कार्ड की संख्या भी कम है, लेकिन अन्नपूर्णा कार्ड से अधिक है इसकी संख्या 9767 है। प्राथमिकता कार्ड की संख्या सबसे अधिक 4202536 है। एपीएल सामान्य परिवार की राशनकार्ड की संख्या 877958 है।

तालिका क्रमांक 2 : छत्तीसगढ़ में जातिवार राशनकार्ड की जानकारी

क्रमांक	राशन कार्ड	ग्रामीण	शहरी	कुल योग
1.	अनुसूचित जाति	736067	174123	910190
2.	अनुसूचित जनजाति	1847030	124653	1971683
3.	अन्य पिछड़ा वर्ग	2442045	653353	3095398
4.	सामान्य	189815	362915	552730

(स्रोत : छत्तीसगढ़ खाद्य विभाग)

उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट होता है कि अनुसूचित जाति की ग्रामीण राशनकार्ड की संख्या 736067 तथा शहरी राशनकार्ड की संख्या 174123 तथा कुल योग 910190 है। इसी तरह अनुसूचित जनजाति की ग्रामीण संख्या 1847030 तथा शहरी संख्या 124653 तथा योग 1971683 है। अन्य पिछड़ा वर्ग की ग्रामीण संख्या 2442045 तथा शहरी संख्या 653353 तथा योग 3095398 है, तथा सामान्य वर्ग की ग्रामीण संख्या 189815 शहरी संख्या 362915 तथा योग 552730 है।

तालिका क्रमांक 3 : छत्तीसगढ़ में शहरी एवं ग्रामीण दुकानों की संख्या

क्र.	शहरी दुकानों की संख्या	ग्रामीण दुकानों की संख्या	कुल दुकानों की संख्या
1.	1262	11047	12309

निष्कर्ष

संपूर्ण आंकड़ों का अध्ययन करने के पश्चात् यह निष्कर्ष निकलता है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली गरीब, असहाय लोगों के लिए वरदान साबित हुई हैं। जो कि राज्य तथा देश की सबसे बड़ी समस्या गरीबी तथा भुखमरी को समाप्त करने में काफी कारगर भूमिका निभा रही हैं। आज पी.डी.एस. का इतना व्यापक रूप गरीबी और भुखमरी

को जड़ से उखाड़ फेंकने हेतु सरकार के प्रयासों को दर्शा रही है। "सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए छत्तीसगढ़ को मिलने वाला राष्ट्रीय पुरस्कार, मुख्य रूप से राज्य सरकार द्वारा किए गए निरंतर एवं अथक प्रयासों का परिणाम है। हमारे तत्कालीन प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेन्द्र मोदी जी ने छत्तीसगढ़ की सार्वजनिक वितरण प्रणाली को देश की सबसे अच्छी वितरण प्रणाली कहा है। इस प्रणाली में संशोधन करते समय 01 जून 1997 को भारत सरकार द्वारा उपभोक्ताओं को खाद्यान्न, शक्कर, केरोसिन आदि वस्तुएं उचित दर पर, उचित मूल्य के दुकानों के माध्यम से उपलब्ध कराने हेतु, लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली लागू की गयी और इसी उद्देश्य को तेजी से पूरा करने के लिए छत्तीसगढ़ राज्य शासन द्वारा 23 सितम्बर 2004 को प्रदेश में छत्तीसगढ़ सार्वजनिक वितरण प्रणाली नियोजन आदेश 2004 लागू किया गया। समय के साथ प्रणाली में पारदर्शिता और उपभोक्ताओं को अधिक सुविधा प्रदान करने के लिए उचित मूल्य की दुकानों में ऑनलाइन सेवाएं वर्ष 2007 से शुरू कर दी गयी। इस प्रकार छत्तीसगढ़ सरकार लगातार वितरण प्रणाली में सुधार करती रही है और यही प्रयास राज्य सरकार को अभी तक 7 राष्ट्रीय स्तर के पुरस्कार दिला चुकी है जिसमें पी.एम. अवार्ड 2008-09 सहित अन्य अवार्ड शामिल है। आज पूरे देश में प्रथम स्थान पर आरूढ़ छत्तीसगढ़ की वितरण प्रणाली सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है"। इसी के साथ महिला सशक्तिकरण एवं महिलाओं को आगे लाने के लिए सरकार ने बहुत अधिक योजनाएं लागू की जिसमें से सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत महिला हितग्राहियों के नाम से ही राशनकार्ड बनाना अति सराहनीय प्रयास रहा है।

संदर्भ सूची

1. छत्तीसगढ़ शासन खाद्य विभाग (2018)।
2. कुमेटी, आशीष एवं घनश्याम (2018) *छत्तीसगढ़ दर्शन*।
3. चौहान, उमेश. (2014) *भारत में खाद्य सुरक्षा एवं कृषि*।
4. अग्रवाल, ए.एन. (2018) *भारतीय अर्थव्यवस्था*।
5. मिश्रा, चंद्रशेखर. (1991) *सार्वजनिक वितरण प्रणाली प्रबंधन में सुधार आवश्यक*।
6. सक्सेना, जगदीप. (2017) *भारत में खाद्य सुरक्षा दशा दिशा और भावी परिदृश्य*।
7. विकीपीडिया
8. khadya.cgnic.in
9. nfsa.Samagra.gov.in
